

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक:- प. 8(2)(7)निर्वा./2023/2494

जयपुर, दिनांक 26.6.2023

प्रेषक:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित:- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर्स) राजस्थान।

विषय:- **Instruction on Vulnerability Mapping, Critical Polling Stations and preventive measures – regarding.**

प्रसंग:- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक No.464/L&O/2023/EPS (VM) दिनांक 21.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने अपने प्रासंगिक पत्र दिनांक 21.06.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। विश्वास बहाली के उपायों के लिए प्रयासों और संसाधनों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान और **भेद्यता मानचित्रण का अभ्यास (exercise of vulnerability mapping)** ऐसा ही एक उपाय है, और प्रत्येक मतदाता के लिए मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना, बिना किसी बाधा के या किसी के द्वारा अनावश्यक रूप से प्रभावित या भयभीत किए बिना मतदान केन्द्र तक पहुंचना।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और पिछले सभी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उपरोक्त सन्दर्भ के तहत आयोग द्वारा एक संशोधित समेकित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं :-

A. Vulnerability Mapping :

चुनावों के सन्दर्भ में Vulnerability को किसी भी मतदाता या मतदाताओं के वर्ग की संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, चाहे वह भौगोलिक रूप से पहचाने गए क्षेत्र में रह रहा हो या नहीं, उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से वोट देने के अधिकार के प्रयोग के संबंध में डराने-धमकाने या अनुचित प्रभाव या किसी भी प्रकार के बल का उपयोग करके गलत तरीके से रोका जा सकता है या उस पर प्रभाव डाला जा सकता है।

Vulnerability Mapping (VM) का उद्देश्य ऐसे मतदाताओं या मतदाताओं के उस वर्ग की पहचान से पहचान करना है जो असुरक्षित होने की संभावना रखते हैं, ऐसी Vulnerable पैदा करने वाले व्यक्तियों या अन्य कारकों की पहचान करना और/या गांवों/बस्तियों/आवासों और खंडों की पहचान करना है। मतदाता चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग के विरुद्ध किसी भी तरह की धमकी, धमकी या हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील हो और उसके लिए पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई करें।

A.1 Stages of Vulnerability Mapping Exercise:

- i. मतदाताओं/मतदाता खंडों, गांव/बस्तियों/क्षेत्रवार, खतरे या डराने-धमकाने के प्रति संवेदनशील या प्रभाव में रहने वाले मतदाताओं की पहचान।

- ii. बाहुबल/धनबल का उपयोग करके ऐसी भेद्यता (Vulnerability) पैदा करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना।
- iii. असुरक्षा पैदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ निवारक उपाय शुरू करना।

A.2 Parameters of Vulnerability:

Vulnerability Mapping का कार्य पिछले आम चुनाव के लिए निर्धारित मतदान की तारीख से 06 महीने पहले शुरू हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) जिले में वर्तमान और पिछले चुनावों के आधार पर निर्धारित प्रोफार्मा (Annexure-I) में Vulnerability के मापदंडों पर इनपुट एकत्र करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पैरा A.3.1 के अनुसार नियुक्त सैक्टर अधिकारी और सैक्टर पुलिस अधिकारी को चुनाव पूर्व सत्यापित शिकायतों और निजी सम्पत्तियों के विरूपण के मामलों, यदि कोई हो, की जानकारी के साथ Annexure-I में यह जानकारी प्रदान करेगा।

A.3 Action to be taken under Vulnerability Mapping :

A.3.1 Appointment of Sector Officer:

पिछले आम चुनाव के लिए निर्धारित मतदान की तारीख से 4 महीने पहले एक सैक्टर अधिकारी और सैक्टर पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। Vulnerability Mapping के लिए सैक्टर अधिकारी और सैक्टर पुलिस अधिकारी को उनके रोल, जिम्मेदारियों और गतिविधियों की समय-सीमा पर उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसा कि Vulnerability Mapping (नवीनतम संस्करण) मैनुअल में प्रदान किया गया है।

A.3.2 Identification of Vulnerable Voters/Segments and the persons causing such vulnerability :

Annexure-I में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुटों के आधार पर, सैक्टर पुलिस अधिकारी के साथ सैक्टर अधिकारी नियमित अन्तराल पर क्षेत्र का दौरा करेंगे और Vulnerability Mapping पर इनपुट देंगे और मतदाताओं/मतदाता खंडों की पहचान करेंगे जो धमकी या डराने-धमकाने या अनुचित प्रभाव आदि के प्रति संवेदनशील हैं। ये अधिकारी मतदाताओं/क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की भी पहचान करेंगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर गांव, छोटे गांव (Hamlet), सम्भावित उपद्रवियों के नाम, उनके सम्पर्क नम्बर, पता आदि का उल्लेख करना होगा। यदि वांछित हो तो मुखबिरों/स्त्रोतों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए यह कार्य किया जाना है।

A.3.3 Other Avenues for collecting inputs:

जिला निर्वाचन अधिकारी समग्र दृष्टिकोण लेने के लिए, Vulnerability Mapping के लिए राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत चिंता सूचियों (worry lists) पर विचार करेंगे। राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों से प्राप्त इनपुट को जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्तर तक जाने से पहले एसडीएम स्तर (और इससे नीचे नहीं) पर मान्य किया जा सकता है। इसी प्रकार, मतदाताओं से जानकारी इकट्ठा करने के लिए कॉल सेन्टर/कन्ट्रोल रूम के माध्यम से एक चैनल बनाया जाएगा क्योंकि वे चुनाव में सबसे बड़े हितधारक हैं। जिला पुलिस की जिला खुफिया शाखा से भी इनपुट लिया जाएगा।

Vulnerability Mapping की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, अपेक्षाकृत उच्च प्रशासनिक/पुलिस स्तर पर जानकारी एकत्र करने, कॉस सत्यापन और मिलान करने की एक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

A.3.4 Reports on Vulnerability Mapping:

सैक्टर अधिकारियों/रिटर्निंग ऑफिसरों/जिला निर्वाचन अधिकारियों/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी Vulnerability Mapping रिपोर्ट के प्रारूप, प्रत्येक गतिविधि के लिए समय-सीमा के साथ Vulnerability Mapping (नवीनतम संस्करण) पर मैन्युअल में दिए गए हैं। आयोग का संबंधित क्षेत्रीय प्रभाग मतदान दिवस से पहले पर्यवेक्षकों से विशिष्ट और केन्द्रित इनपुट लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट की जांच करेगा।

A.4 Preventive Measures in Vulnerable areas or against persons causing vulnerability :

यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि कमजोर व्यक्ति, यदि कोई हो, बिना किसी डर, धमकी, अनुचित प्रभाव या धमकी के मतदान करने में सक्षम हो :-

- I. जिला निर्वाचन अधिकारी और जिले के CP/SP एक संयुक्त समीक्षा के माध्यम से पहचाने गए सम्भावित खतरों और डराने-धमकाने वाले बिन्दुओं से निपटने के लिए एक कार्य योजना को अन्तिम रूप देंगे। कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ पहचाने गए उपद्रवियों को कानून की उचित धारा के तहत प्रतिबन्धित करना शामिल हो सकता है; अवैध हथियारों की जब्ती, यदि आवश्यक हो तो निवारक निरोध; उनका अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उचित अन्तराल पर स्थानीय पुलिस स्टेशनों में उपस्थित होने के लिए बाध्य करना; लाईसेंसी हथियारों को जमा करना; पुलिस पिकेट (Police pickets) की नियुक्ति और विश्वास बहाली के उपाय करना। **मतदान के दिन मतदाताओं को डराने-धमकाने या बाधा डालने की घटना न हो, इसके लिए अन्तिम 72 घण्टों में विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।**
- II. यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे सभी उपाय किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रति भय या पक्षपात के बिना बिल्कुल गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से किए जाएं।
- III. संवेदनशील स्थानों, संवेदनशील मतदाताओं और संवेदनशीलता पैदा करने वाले मतदाताओं की सूची के सन्दर्भ में VM4-RO रिपोर्ट (Ref: latest edition of Manual on Vulnerability Mapping) का उपयोग किसी भी निवारक उपाय आदि के लिए किया जा सकता है।
- IV. सैक्टर अधिकारी और मोबाईल सुरक्षा बल मतदान के दिन कम से कम एक बार ऐसे गांवों/हेमलेट्स/आवासीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जिन्हें संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। सैक्टर अधिकारी और सैक्टर पुलिस अधिकारी जहां भी आवश्यक हो, कमजोर मतदाताओं को पर्याप्त सुरक्षा कवर प्रदान करेंगे।
- V. पर्यवेक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, मतदान के दिन मतदान केन्द्रों का दौरा करते समय, कमजोर मतदाताओं की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देंगे और अपने संबंधित मतदान केन्द्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।
- VI. पुलिस गश्ती दल संवेदनशील स्थानों पर नजर रखेंगे और नियन्त्रण कक्ष को सूचित करते रहेंगे।
- VII. सीएपीएफ के कमांडर/सहायक कमांडर मतदान के दिन तक विश्वास बहाली के उपाय के रूप में ऐसे कमजोर इलाकों का दौरा करना सुनिश्चित करेंगे। यदि उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो वे उस पर ध्यान देंगे और किसी भी अधिकारी जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक/पर्यवेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर/सैक्टर अधिकारी को तुरन्त सूचित करेंगे।

B. Critical Polling Stations :

आयोग ने कुछ वस्तुनिष्ठ मानदण्डों (Annexure-II) के आधार पर मतदान केन्द्रों को संवेदनशील और गैर संवेदनशील में वर्गीकृत करने के लिए उन्नत सुरक्षा उपायों जैसे पर्याप्त सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती को सुनिश्चित करना या अतिरिक्त सिविल उपाय जैसे वेबकास्टिंग आदि को निर्धारित किया है, जिससे चुनाव के संचालन के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी मतदान केन्द्र को एक संवेदनशील मतदान केन्द्र के रूप में निर्धारित करने के लिए ऐसे वस्तुनिष्ठ मानदण्डों में से एक, Vulnerability Area में पहचाने गए मतदान केन्द्र एवं संवेदनशील पॉकेट/बस्तियों/गांव आदि में स्थित मतदान केन्द्र में पाया जाना चाहिए। अतः Vulnerability Mapping के तहत पहचाने गए सभी मतदान केन्द्रों को संवेदनशील मतदान केन्द्रों के रूप में नामित किया जाएगा।

अभी और स्पष्ट करने के लिए, Vulnerability Mapping, संवेदनशील मतदाताओं और क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक सक्रिय, चुनाव – पूर्व अभ्यास है और मतदान के दिन से पहले ही जोखिम पैदा करने वाले कारकों को कम करने के लिए लागू किया जाने वाला निवारक उपाय है जबकि संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान पिछले चुनावी इतिहास के आधार पर की जाती है जिससे उक्त चिन्हित मतदान केन्द्रों पर उन्नत उपाय लागू कर चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और चुनावी हिंसा को रोका जा सके।

B.1 Measures to be taken for critical polling stations:

- i. सभी क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर अधिकतम सम्भव सीमा तक मतदान केन्द्रों की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की तैनाती होगी।
- ii. ऐसे सभी क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की सूची सीएपीएफ के कमांडिंग/सहायक कमांडिंग अधिकारियों को दी जाएगी ताकि वे ऐसे मतदान केन्द्रों पर नजर रख सकें।
- iii. नागरिक उपाय के रूप में मतदान केन्द्र में वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी और किसी अन्य निगरानी प्रणाली की तैनाती की जाएगी। सभी क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर या सहायक मतदान केन्द्रों सहित कुल मतदान केन्द्रों के कम से कम 50% में, जो भी अधिक हो, वेबकास्टिंग की जाएगी।
- iv. मतदान केन्द्र और उसके आस-पास महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।
- v. निगरानी बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त नागरिक उपाय के रूप में, संवेदनशील मतदान केन्द्र के अन्दर एक माइक्रो पर्यवेक्षक तैनात किया जा सकता है।
- vi. क्रिटिकल मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी कि ईपिक/अनुमोदित पहचान दस्तावेज, यदि कोई है, ठीक से सत्यापित है और फार्म 17 ए के 'टिप्पणी' कॉलम में परिलक्षित होता है।

C. Role of Observers/DEO/RO:

- i. जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर नियमित रूप से फीडबैक इकट्ठा करने के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। जिला खुफिया शाखा एसपी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को मतदाताओं और क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की संवेदनशीलता के विषय पर नियमित फीडबैक भी देगी।
- ii. निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक के आगमन पर, DEO/RO संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/खंड के मतदान केन्द्रवार Vulnerability

Mapping, का विवरण और क्रिटीकल मतदान केन्द्रों की सूची पर्यवेक्षकों को सौंपेगे। अन्तिम सूची को वरिष्ठतम सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

- iii. घटनाक्रम पर लगातार नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक ऐसे स्थानों का दौरा करेंगे और मतदाताओं से बातचीत करेंगे।
- iv. डिस्पैच केन्द्रों से मतदान दलों की रवानगी के समय, रिटर्निंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र के भीतर क्रिटीकल मतदान केन्द्रों और संवेदनशील स्थानों के बारे में जानकारी देगा।
- v. जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर मतदान के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय बड़े पैमाने पर धमकी/बाधा, यदि कोई हो, संबंधी इनपुट को ध्यान में रखेंगे।
- vi. पर्यवेक्षक अपना पूरा ध्यान Vulnerability Mapping और क्रिटीकल पोलिंग स्टेशन के मुद्दे पर देंगे। वे अपनी अंतिम रिपोर्ट में स्थिति का सत्यापन और उल्लेख करेंगे।

D. Accountability and Confidentiality:

आयोग के निर्देश है कि Vulnerability Mapping और क्रिटीकल मतदान केन्द्रों और प्रत्येक चरण पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभिन्न नागरिक और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही प्रत्येक मतदान केन्द्र/निर्वाचन क्षेत्र के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएगी। इस मामले में किसी भी नागरिक/पुलिस अधिकारी की ओर से कर्तव्य में लापरवाही के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चुनाव के दौरान, क्रिटीकल मतदान केन्द्रों, Vulnerability Mapping अभ्यास, संवेदनशील क्षेत्रों, सुरक्षा बलों की तैनाती आदि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवरण प्रस्तुत करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं की जाएगी। इसमें फील्ड मशीनरी को संवेदनशील बनाया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो, Vulnerability के बारे में मीडिया को कोई भी जानकारी केवल आयोग द्वारा आयोग के निर्देश पर संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दी जाएगी।

Vulnerability Mapping और क्रिटीकल मतदान केन्द्रों पर विस्तृत निर्देश कमशः Manual on Vulnerability Mapping (latest edition) और Manual on Force Deployment in Election (latest edition) में शामिल है। विवरण और स्पष्टीकरण के लिए इन मैनुअल का सन्दर्भ लिया जा सकता है।

अतः भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 21 जून, 2023 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि आयोग ने अपने पूर्व में जारी सन्दर्भित समस्त निर्देशों के अधिकमण करते हुए, आगामी विधानसभा आम चुनाव/लोकसभा आम चुनाव/उप चुनावों में आयोग के उक्त नवीनतम विस्तृत दिशा-निर्देशों को संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाकर कड़ाई से पालना सुनिश्चित करायी जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(प्रवीण गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 8(2)(7) / निर्वा / 2023 / 2494

जयपुर, दिनांक: 26.6.2023

प्रतिलिपि निम्न को आयोग के पत्र दिनांक 21.06.2023 की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान।
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिरीक्षक पुलिस (रेंज), जयपुर।
7. महानिरीक्षक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स, राजस्थान, जयपुर।
8. पुलिस आयुक्त, जयपुर एवं जोधपुर।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
10. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।
11. उप विधि परामर्शी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।
12. लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

राजस्थान, जयपुर।

सुरेश चन्द्र

विधेशाधिकारी

निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर



भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Tel. No. 011-23052144
Fax 011-23052001
website: www.eci.gov.in

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan
Ashoka Road, New Delhi-110001
Dated: 21st June, 2023

No.464/L&O/2023/EPS (VM)

To

The Chief Electoral Officers of
All States/UTs

**Subject: Instruction on Vulnerability Mapping, Critical Polling Stations
and preventive measures – regarding.**

Reference:

- | | | | |
|--------|--------------------------------|-------|------------|
| (i) | Letter No. 464/INST/2007-PLN-I | dated | 12.10.2007 |
| (ii) | Letter No. 464/INST/2008/EPS | dated | 24.10.2008 |
| (iii) | Letter No.464/INST/2009-EPS | dated | 22.03.2009 |
| (iv) | Letter No. 464/BR-LA/2010 | dated | 16.10.2010 |
| (v) | Letter No.464/INST/2011/EPS | dated | 05.03.2011 |
| (vi) | Letter No. 464/INST/2011-EPS | dated | 30.12.2011 |
| (vii) | Letter No.464/INST/2014/EPS | dated | 12.03.2014 |
| (viii) | Letter No. 464/L&O/2015-EPS | dated | 21.10.2015 |

Madam/Sir,

The Election Commission of India has issued various instructions on measures to be taken to ensure free and fair elections. One such measure is the exercise of Vulnerability Mapping and identification of Critical Polling Stations to focus efforts and resources for confidence building measures and to create secured environment for every elector to access the Polling Station without being obstructed or being unduly influenced or intimidated by anybody to exercise the franchise without any fear.

2. In view of the above and in supersession of all previous instructions issued by the Commission under reference above, a revised consolidated instruction is hereby issued.

A. VULNERABILITY MAPPING:

Vulnerability in the context of elections may be defined as the susceptibility of any voter or section of voters, whether or not living in a geographically identifiable area, to being wrongfully prevented from or influenced upon in

relation to the exercise of his or her right to vote in a free and fair manner through intimidation or use of undue influence or force of any kind.

The exercise of **Vulnerability Mapping (VM)** is to identify, in advance, such voters or section of voters who are likely to be vulnerable, the persons or other factors causing such vulnerability and/or to identify the villages/hamlets/habitats and segments of electorate vulnerable to any threat, intimidation or interference *against* the free exercise of electoral right and taking adequate corrective action thereof.

A.1 STAGES OF VULNERABILITY MAPPING EXERCISE:

- (i) Identification of the voters/voter segments, village/hamlets/ area wise, vulnerable to threat or intimidation or undue influence.
- (ii) Identification of the persons causing such vulnerability using muscle/ money power.
- (iii) Initiating preventive measures against the persons responsible for causing vulnerability.

A.2 PARAMETERS OF VULNERABILITY:

The exercise of Vulnerability Mapping shall start 6 months before the date of poll fixed for the last held General Election. District Election Officer (DEO) shall collect inputs on parameters of vulnerability in prescribed proforma (**Annexure-I**) based on present and past elections in the district. The DEO shall provide this information in **Annexure-I**, along with the information on pre-poll verified complaints and cases of defacement of private properties, if any, to the Sector Officers and Sector Police Officer as appointed according to para **A.3.1**.

A.3 ACTION TO BE TAKEN UNDER VULNERABILITY MAPPING:

A.3.1 APPOINTMENT OF SECTOR OFFICER:

A Sector Officer and Sector Police Officer shall be appointed 4 months before the date of poll fixed for the last held General Election. Suitable training shall be imparted to the Sector Officer and Sector Police Officer on their roll, responsibilities and timeline of activities for Vulnerability Mapping as provided in the Manual on Vulnerability Mapping (*latest edition*).



A.3.2 IDENTIFICATION OF VULNERABLE VOTERS/SEGMENTS AND THE PERSONS CAUSING SUCH VULNERABILITY:

On the basis of the inputs provided by the DEO in *Annexure-I*, The Sector Officer along with Sector Police Officer shall make field visits at regular intervals and give inputs on Vulnerability Mapping and identify voters/voter segments vulnerable to threat or intimidation or undue influence etc. These Officers shall also identify the persons responsible for making the voters / areas vulnerable, at each polling station indicating the name of village, hamlet, names of the potential troublemakers, including their contact numbers, address etc. This work has to be done by maintaining complete confidentiality of the informers/sources, if so desired.

A.3.3 OTHER AVENUES FOR COLLECTING INPUTS:

The DEO shall consider the worry lists submitted by political parties/candidates for Vulnerability Mapping, to take a holistic view. The inputs from political parties/candidates, so received may be validated at the SDM level (and not below it) before it goes up to the level of DEO. Similarly, a channel shall be created through Call Centers/Control Rooms to gather information from the voters as they are the largest stakeholder in the elections. Inputs from District Intelligence Branch of the District Police shall also be taken.

In order to ensure authenticity of the Vulnerability reporting, a mechanism of collecting, cross verifying, validating and collating information at a relatively higher administrative/ police level shall be ensured.

A.3.4 REPORTS ON VULNERABILITY MAPPING:

The formats of all the Vulnerability Mapping reports to be used by Sector Officers, Returning Officers, DEO and CEO respectively are given in the Manual on Vulnerability Mapping (*latest edition*) along with a timeline for each activity. The same may be referred to for scrupulous compliance. Concerned Zonal Division of the Commission shall scrutinize the report from CEO by taking specific and focused inputs from the Observers before poll day.



A.4 PREVENTIVE MEASURES IN VULNERABLE AREAS OR AGAINST PERSONS CAUSING VULNERABILITY:

Following actions need to be taken to ensure that the vulnerable persons, if any, are able to vote without fear, threat, undue influence or intimidation:

- (i) The DEO and the CP/SP of the District through a joint review shall finalize an action plan to deal with the potential threats and intimidation points identified. The action plan may include *inter alia* bounding down the identified trouble makers under appropriate section of the law; seizure of illegal arms; preventive detention, if required; forcing their appearance in local police stations at reasonable intervals to ensure their good behaviour; deposit of licensed arms; placement of police pickets and carrying out confidence building measures. Special efforts should be taken in the last 72 hours to ensure that intimidation or obstruction of electors does not happen on the poll day.
- (ii) It has to be ensured that all such measures are undertaken in absolutely non-partisan manner without fear or favour towards any particular political party or candidate.
- (iii) The VM4-RO Reports (*Ref: latest edition of Manual on Vulnerability Mapping*) with reference to vulnerable locations, list of vulnerable voters and voters causing vulnerability may be used for undertaking any preventive measures etc.
- (iv) The Sector Officers and the mobile security forces shall visit such villages/hamlets/dwelling areas which are identified as vulnerable areas, at least once on poll day. The Sector Officers and Sector Police Officers shall provide adequate security cover to the vulnerable voters wherever required.
- (v) Observers and other senior officers, while visiting the Polling Stations on poll day, shall pay special attention towards the turnout of vulnerable voters and take necessary measures to provide access to their respective polling stations.
- (vi) The police patrolling parties shall keep track of the vulnerable locations and keep the control room informed.

- (vii) The Commanders/Assistant Commanders of the CAPF shall make it a point to visit such vulnerable pockets as a confidence building measure till the day of poll. In case they come across any suspicious activities, they shall take note of it and immediately inform any of the officials such as DEO/SP/Observer/RO/Sector Officer.

B. CRITICAL POLLING STATIONS:

The Commission has prescribed for categorization of polling stations into **critical** and non-critical based on certain objective criteria (**Annexure-II**) to ensure enhanced security measures such as deployment of sufficient CAPF personnel or provide additional civil measures like webcasting etc. in order to create a secured environment for conduct of elections. **It shall be noted that one of such objective criteria for determining any Polling Station to be a Critical Polling Station is presence of vulnerable pockets/hamlets/ villages etc. in that Polling Station or Polling Station located in identified vulnerable areas. Therefore, all Polling Stations identified under Vulnerability Mapping shall be designated as Critical Polling Stations.**

Just to further clarify, Vulnerability Mapping is *pro-active* pre-poll exercise to identify vulnerable voters and areas and enforcing preventive measures well before poll day to mitigate the factors causing vulnerability, whereas critical polling stations are identified, based on the past electoral history, to provide focused enhanced measures at identified Polling Stations to prevent poll process vitiation and electoral violence.

B.1 MEASURES TO BE TAKEN FOR CRITICAL POLLING STATIONS:

- (i) All critical Polling Stations shall have CAPF deployment to safeguard the Polling Stations to the maximum possible extent.
- (ii) The list of all such critical Polling Stations shall be given to the Commanding/Assistant Commanding Officers of CAPF so that they can keep a watch on such Polling Stations.
- (iii) Deployment of webcasting or videography and any other monitoring system shall be positioned in the Polling Station as a civil measure. **Webcasting shall be done in all critical polling**

stations or at least in 50% of total polling stations including auxiliary polling stations, whichever is higher.

- (iv) Critical events in and around the polling station shall also be videographed.
- (v) A Micro Observer may be deployed inside the critical Polling Station, as additional civil measure, to enhance monitoring.
- (vi) The Presiding Officer of critical Polling Station shall be specifically briefed to ensure that the EPIC/ approved identification document, if any, are properly verified and reflected in the 'Remarks' column of Form 17 A.

C. ROLE OF OBSERVERS/ DEO/RO:

- (i) The DEO/ RO shall interact with the candidates and representatives of political parties to gather regular feedback. The District Intelligence Branch shall also give regular feedback on the subject of vulnerability of voters and critical Polling Stations to the DEO through SP.
- (ii) Upon the arrival of the General Observer, Police Observer and Expenditure Observer in the Constituency, the DEO/RO shall brief and hand over the details of polling station-wise Vulnerability Mapping of the relevant Assembly Constituency/Segment and a list of critical Polling Stations to the Observers. The final list shall be approved by the senior most General and Police Observers.
- (iii) The Observers shall visit such locations and interact with the voters in order to constantly monitor the developments.
- (iv) At the time of dispatch of the polling parties from the dispatch centres, the RO shall brief the Presiding Officer concerned regarding the critical Polling Stations and vulnerable locations within the Polling Station area.
- (v) The DEO/RO shall take the inputs on mass scale intimidation/ threat/obstruction, if any, into consideration while submitting their report after the poll.



- (vi) The Observers shall give their full attention to the issue of Vulnerability Mapping and critical Polling Station. They shall verify and make a mention of the situation in their final report.

D. ACCOUNTABILITY AND CONFIDENTIALITY:

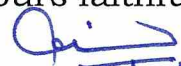
The Commission directs that accountability of various civil and police officials for Vulnerability Mapping and critical Polling Stations and follow-up at every stage shall be clearly defined with reference to each Polling Station/Constituency. Disciplinary action shall be initiated in case of dereliction of duty on the part of any civil/police officials in this matter.

It is to be noted that during elections, no press conference of any kind shall be held to furnish any type of details relating to critical Polling Stations, Vulnerability Mapping exercise, vulnerable areas, deployment of security forces etc. Field machinery shall be sensitized in this regard. Any information to media about vulnerability, if required, would be given only by the Commission or by the Chief Electoral Officers of the State/ UTs concerned on instructions of the Commission.

Detailed instructions on Vulnerability Mapping and Critical Polling Stations are contained in Manual on Vulnerability Mapping (*latest edition*) and Manual on Force Deployment in Election (*latest edition*), respectively. These Manuals may be referred for details and clarifications.

This shall be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,


21/06/2023

(SANJEEV KUMAR PRASAD)
SECRETARY

Copy to:

All Sr.DECs/ DECs/ Sr.Pr.Secy/ Directors/ Pr.Secy/ Secretary/ Zonal Divisions

Format VM-1**Information on each AC/Sector to be provided by DEO to Sector Officer before he/she undertakes the exercise of VM**

1. Number of election offences registered in the last parliamentary elections in the AC/Sector (give details wherever required)
2. Number of election offences registered in the last assembly election in the AC/Sector (give details wherever required)
3. Number of election offences registered in the last local body election in the AC/Sector (give details wherever required)
4. Number of serious criminal offences, caste conflicts, and communal incidents registered in the area, if any, in the last one year (give details wherever required)
5. Model code of conduct violations if any in the last parliamentary election (give details wherever required)
6. Model code of conduct violations if any, in the last assembly elections (give details wherever required)
7. Number of incidents of cash/kind seized/intercepted by FSTs/SSTs in the last parliamentary election (Give details whenever required) and details of expenditure sensitive pockets in the last parliamentary election
8. Number of incidents of cash/kind seized/intercepted by FSTs/SSTs in the last assembly election (Give details whenever required) and details of expenditure sensitive pockets in the last assembly election
9. Details of re-poll if any in the last general election of parliament or assembly or any bye-election
10. Details of Prohibition laws related cases in the last parliamentary/assembly and local elections.
11. Names of persons from AC/Sector currently under externment /detention.
12. No. of cases & details of important cases registered in the area under relevant State Excise Act:
 - (i) In the last parliament election.
 - (ii) In the last Assembly election.
 - (iii) In the last one year
13. Arms related information
14. Details of cases violating the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act
15. List of warranties of area in election related cases.
16. List of habitual offenders (with details of crime) of that area

- 17.** Details of pre-poll complaints if any related to electoral rolls of the AC/sector
- 18.** Details of any other pre-poll complaints
- 19.** Information regarding more than normal migration in the last 06 months to and from the AC/Sector, if any
- 20.** Voter turnout and % in the last Parliamentary elections along with voter turnout details of allocated Polling Stations:
 - Male:
 - Female:
 - Overall:
- 21.** Voter turnout and with % in the last assembly elections along with voter turnout details of allocated Polling Stations:
 - Male:
 - Female:
 - Overall:



Annexure-II

OBJECTIVE CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF CRITICAL POLLING STATIONS:

- (i) PSs having vulnerable pockets and PSs located in identified vulnerable area.
- (ii) PSs where polling was more than 90% and where more than 75% of votes have been polled in favour of one candidate in last election.
- (iii) PSs where polling is less than 10%
- (iv) PSs where Re-poll conducted owing to vitiation of poll process and electoral offences such as booth capturing, during any election for Lok Sabha or State Legislative Assembly in last five years
- (v) PSs where any sort of violence tookplace on poll day leading to lodging of FIR, during any election for Lok Sabha or State Legislative Assembly in last five years.
- (vi) PSs with higher than constituency average % of Absentee, Shifted and Dead (ASD) voters (*Ref: Constituency Average % of ASD Voters=Total number of ASD Voters in the constituency/ Total number of polling station*)
- (vii) Information regarding abnormal law and order situation in any particular area.



भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Tel. No. 011-23052144
Fax 011-23052001
website: www.eci.gov.in

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan
Ashoka Road, New Delhi-110001
Dated: 21st June, 2023

No.464/L&O/2023/EPS (VM)

To

The Chief Electoral Officers of
All States/UTs

**Subject: Instruction on Vulnerability Mapping, Critical Polling Stations
and preventive measures – regarding.**

Reference:

- | | | | |
|--------|--------------------------------|-------|------------|
| (i) | Letter No. 464/INST/2007-PLN-I | dated | 12.10.2007 |
| (ii) | Letter No. 464/INST/2008/EPS | dated | 24.10.2008 |
| (iii) | Letter No.464/INST/2009-EPS | dated | 22.03.2009 |
| (iv) | Letter No. 464/BR-LA/2010 | dated | 16.10.2010 |
| (v) | Letter No.464/INST/2011/EPS | dated | 05.03.2011 |
| (vi) | Letter No. 464/INST/2011-EPS | dated | 30.12.2011 |
| (vii) | Letter No.464/INST/2014/EPS | dated | 12.03.2014 |
| (viii) | Letter No. 464/L&O/2015-EPS | dated | 21.10.2015 |

Madam/Sir,

The Election Commission of India has issued various instructions on measures to be taken to ensure free and fair elections. One such measure is the exercise of Vulnerability Mapping and identification of Critical Polling Stations to focus efforts and resources for confidence building measures and to create secured environment for every elector to access the Polling Station without being obstructed or being unduly influenced or intimidated by anybody to exercise the franchise without any fear.

2. In view of the above and in supersession of all previous instructions issued by the Commission under reference above, a revised consolidated instruction is hereby issued.

A. VULNERABILITY MAPPING:

Vulnerability in the context of elections may be defined as the susceptibility of any voter or section of voters, whether or not living in a geographically identifiable area, to being wrongfully prevented from or influenced upon in

relation to the exercise of his or her right to vote in a free and fair manner through intimidation or use of undue influence or force of any kind.

The exercise of **Vulnerability Mapping (VM)** is to identify, in advance, such voters or section of voters who are likely to be vulnerable, the persons or other factors causing such vulnerability and/or to identify the villages/hamlets/habitats and segments of electorate vulnerable to any threat, intimidation or interference *against* the free exercise of electoral right and taking adequate corrective action thereof.

A.1 STAGES OF VULNERABILITY MAPPING EXERCISE:

- (i) Identification of the voters/voter segments, village/hamlets/ area wise, vulnerable to threat or intimidation or undue influence.
- (ii) Identification of the persons causing such vulnerability using muscle/ money power.
- (iii) Initiating preventive measures against the persons responsible for causing vulnerability.

A.2 PARAMETERS OF VULNERABILITY:

The exercise of Vulnerability Mapping shall start 6 months before the date of poll fixed for the last held General Election. District Election Officer (DEO) shall collect inputs on parameters of vulnerability in prescribed proforma (**Annexure-I**) based on present and past elections in the district. The DEO shall provide this information in **Annexure-I**, along with the information on pre-poll verified complaints and cases of defacement of private properties, if any, to the Sector Officers and Sector Police Officer as appointed according to para **A.3.1**.

A.3 ACTION TO BE TAKEN UNDER VULNERABILITY MAPPING:

A.3.1 APPOINTMENT OF SECTOR OFFICER:

A Sector Officer and Sector Police Officer shall be appointed 4 months before the date of poll fixed for the last held General Election. Suitable training shall be imparted to the Sector Officer and Sector Police Officer on their roll, responsibilities and timeline of activities for Vulnerability Mapping as provided in the Manual on Vulnerability Mapping (*latest edition*).



A.3.2 IDENTIFICATION OF VULNERABLE VOTERS/SEGMENTS AND THE PERSONS CAUSING SUCH VULNERABILITY:

On the basis of the inputs provided by the DEO in *Annexure-I*, The Sector Officer along with Sector Police Officer shall make field visits at regular intervals and give inputs on Vulnerability Mapping and identify voters/voter segments vulnerable to threat or intimidation or undue influence etc. These Officers shall also identify the persons responsible for making the voters / areas vulnerable, at each polling station indicating the name of village, hamlet, names of the potential troublemakers, including their contact numbers, address etc. This work has to be done by maintaining complete confidentiality of the informers/sources, if so desired.

A.3.3 OTHER AVENUES FOR COLLECTING INPUTS:

The DEO shall consider the worry lists submitted by political parties/candidates for Vulnerability Mapping, to take a holistic view. The inputs from political parties/candidates, so received may be validated at the SDM level (and not below it) before it goes up to the level of DEO. Similarly, a channel shall be created through Call Centers/Control Rooms to gather information from the voters as they are the largest stakeholder in the elections. Inputs from District Intelligence Branch of the District Police shall also be taken.

In order to ensure authenticity of the Vulnerability reporting, a mechanism of collecting, cross verifying, validating and collating information at a relatively higher administrative/ police level shall be ensured.

A.3.4 REPORTS ON VULNERABILITY MAPPING:

The formats of all the Vulnerability Mapping reports to be used by Sector Officers, Returning Officers, DEO and CEO respectively are given in the Manual on Vulnerability Mapping (*latest edition*) along with a timeline for each activity. The same may be referred to for scrupulous compliance. Concerned Zonal Division of the Commission shall scrutinize the report from CEO by taking specific and focused inputs from the Observers before poll day.



A.4 PREVENTIVE MEASURES IN VULNERABLE AREAS OR AGAINST PERSONS CAUSING VULNERABILITY:

Following actions need to be taken to ensure that the vulnerable persons, if any, are able to vote without fear, threat, undue influence or intimidation:

- (i) The DEO and the CP/SP of the District through a joint review shall finalize an action plan to deal with the potential threats and intimidation points identified. The action plan may include *inter alia* bounding down the identified trouble makers under appropriate section of the law; seizure of illegal arms; preventive detention, if required; forcing their appearance in local police stations at reasonable intervals to ensure their good behaviour; deposit of licensed arms; placement of police pickets and carrying out confidence building measures. Special efforts should be taken in the last 72 hours to ensure that intimidation or obstruction of electors does not happen on the poll day.
- (ii) It has to be ensured that all such measures are undertaken in absolutely non-partisan manner without fear or favour towards any particular political party or candidate.
- (iii) The VM4-RO Reports (*Ref: latest edition of Manual on Vulnerability Mapping*) with reference to vulnerable locations, list of vulnerable voters and voters causing vulnerability may be used for undertaking any preventive measures etc.
- (iv) The Sector Officers and the mobile security forces shall visit such villages/hamlets/dwelling areas which are identified as vulnerable areas, at least once on poll day. The Sector Officers and Sector Police Officers shall provide adequate security cover to the vulnerable voters wherever required.
- (v) Observers and other senior officers, while visiting the Polling Stations on poll day, shall pay special attention towards the turnout of vulnerable voters and take necessary measures to provide access to their respective polling stations.
- (vi) The police patrolling parties shall keep track of the vulnerable locations and keep the control room informed.

- (vii) The Commanders/Assistant Commanders of the CAPF shall make it a point to visit such vulnerable pockets as a confidence building measure till the day of poll. In case they come across any suspicious activities, they shall take note of it and immediately inform any of the officials such as DEO/SP/Observer/RO/Sector Officer.

B. CRITICAL POLLING STATIONS:

The Commission has prescribed for categorization of polling stations into **critical** and non-critical based on certain objective criteria (**Annexure-II**) to ensure enhanced security measures such as deployment of sufficient CAPF personnel or provide additional civil measures like webcasting etc. in order to create a secured environment for conduct of elections. **It shall be noted that one of such objective criteria for determining any Polling Station to be a Critical Polling Station is presence of vulnerable pockets/hamlets/ villages etc. in that Polling Station or Polling Station located in identified vulnerable areas. Therefore, all Polling Stations identified under Vulnerability Mapping shall be designated as Critical Polling Stations.**

Just to further clarify, Vulnerability Mapping is *pro-active* pre-poll exercise to identify vulnerable voters and areas and enforcing preventive measures well before poll day to mitigate the factors causing vulnerability, whereas critical polling stations are identified, based on the past electoral history, to provide focused enhanced measures at identified Polling Stations to prevent poll process vitiation and electoral violence.

B.1 MEASURES TO BE TAKEN FOR CRITICAL POLLING STATIONS:

- (i) All critical Polling Stations shall have CAPF deployment to safeguard the Polling Stations to the maximum possible extent.
- (ii) The list of all such critical Polling Stations shall be given to the Commanding/Assistant Commanding Officers of CAPF so that they can keep a watch on such Polling Stations.
- (iii) Deployment of webcasting or videography and any other monitoring system shall be positioned in the Polling Station as a civil measure. **Webcasting shall be done in all critical polling**

stations or at least in 50% of total polling stations including auxiliary polling stations, whichever is higher.

- (iv) Critical events in and around the polling station shall also be videographed.
- (v) A Micro Observer may be deployed inside the critical Polling Station, as additional civil measure, to enhance monitoring.
- (vi) The Presiding Officer of critical Polling Station shall be specifically briefed to ensure that the EPIC/ approved identification document, if any, are properly verified and reflected in the 'Remarks' column of Form 17 A.

C. ROLE OF OBSERVERS/ DEO/RO:

- (i) The DEO/ RO shall interact with the candidates and representatives of political parties to gather regular feedback. The District Intelligence Branch shall also give regular feedback on the subject of vulnerability of voters and critical Polling Stations to the DEO through SP.
- (ii) Upon the arrival of the General Observer, Police Observer and Expenditure Observer in the Constituency, the DEO/RO shall brief and hand over the details of polling station-wise Vulnerability Mapping of the relevant Assembly Constituency/Segment and a list of critical Polling Stations to the Observers. The final list shall be approved by the senior most General and Police Observers.
- (iii) The Observers shall visit such locations and interact with the voters in order to constantly monitor the developments.
- (iv) At the time of dispatch of the polling parties from the dispatch centres, the RO shall brief the Presiding Officer concerned regarding the critical Polling Stations and vulnerable locations within the Polling Station area.
- (v) The DEO/RO shall take the inputs on mass scale intimidation/ threat/obstruction, if any, into consideration while submitting their report after the poll.



- (vi) The Observers shall give their full attention to the issue of Vulnerability Mapping and critical Polling Station. They shall verify and make a mention of the situation in their final report.

D. ACCOUNTABILITY AND CONFIDENTIALITY:

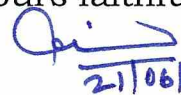
The Commission directs that accountability of various civil and police officials for Vulnerability Mapping and critical Polling Stations and follow-up at every stage shall be clearly defined with reference to each Polling Station/Constituency. Disciplinary action shall be initiated in case of dereliction of duty on the part of any civil/police officials in this matter.

It is to be noted that during elections, no press conference of any kind shall be held to furnish any type of details relating to critical Polling Stations, Vulnerability Mapping exercise, vulnerable areas, deployment of security forces etc. Field machinery shall be sensitized in this regard. Any information to media about vulnerability, if required, would be given only by the Commission or by the Chief Electoral Officers of the State/ UTs concerned on instructions of the Commission.

Detailed instructions on Vulnerability Mapping and Critical Polling Stations are contained in Manual on Vulnerability Mapping (*latest edition*) and Manual on Force Deployment in Election (*latest edition*), respectively. These Manuals may be referred for details and clarifications.

This shall be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,



21/06/2023

(SANJEEV KUMAR PRASAD)
SECRETARY

Copy to:

All Sr.DECs/ DECs/ Sr.Pr.Secy/ Directors/ Pr.Secy/ Secretary/ Zonal Divisions

Format VM-1**Information on each AC/Sector to be provided by DEO to Sector Officer before he/she undertakes the exercise of VM**

1. Number of election offences registered in the last parliamentary elections in the AC/Sector (give details wherever required)
2. Number of election offences registered in the last assembly election in the AC/Sector (give details wherever required)
3. Number of election offences registered in the last local body election in the AC/Sector (give details wherever required)
4. Number of serious criminal offences, caste conflicts, and communal incidents registered in the area, if any, in the last one year (give details wherever required)
5. Model code of conduct violations if any in the last parliamentary election (give details wherever required)
6. Model code of conduct violations if any, in the last assembly elections (give details wherever required)
7. Number of incidents of cash/kind seized/intercepted by FSTs/SSTs in the last parliamentary election (Give details whenever required) and details of expenditure sensitive pockets in the last parliamentary election
8. Number of incidents of cash/kind seized/intercepted by FSTs/SSTs in the last assembly election (Give details whenever required) and details of expenditure sensitive pockets in the last assembly election
9. Details of re-poll if any in the last general election of parliament or assembly or any bye-election
10. Details of Prohibition laws related cases in the last parliamentary/assembly and local elections.
11. Names of persons from AC/Sector currently under externment /detention.
12. No. of cases & details of important cases registered in the area under relevant State Excise Act:
 - (i) In the last parliament election.
 - (ii) In the last Assembly election.
 - (iii) In the last one year
13. Arms related information
14. Details of cases violating the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act
15. List of warranties of area in election related cases.
16. List of habitual offenders (with details of crime) of that area

- 17.** Details of pre-poll complaints if any related to electoral rolls of the AC/sector
- 18.** Details of any other pre-poll complaints
- 19.** Information regarding more than normal migration in the last 06 months to and from the AC/Sector, if any
- 20.** Voter turnout and % in the last Parliamentary elections along with voter turnout details of allocated Polling Stations:
 - Male:
 - Female:
 - Overall:
- 21.** Voter turnout and with % in the last assembly elections along with voter turnout details of allocated Polling Stations:
 - Male:
 - Female:
 - Overall:



Annexure-II

OBJECTIVE CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF CRITICAL POLLING STATIONS:

- (i) PSs having vulnerable pockets and PSs located in identified vulnerable area.
- (ii) PSs where polling was more than 90% and where more than 75% of votes have been polled in favour of one candidate in last election.
- (iii) PSs where polling is less than 10%
- (iv) PSs where Re-poll conducted owing to vitiation of poll process and electoral offences such as booth capturing, during any election for Lok Sabha or State Legislative Assembly in last five years
- (v) PSs where any sort of violence tookplace on poll day leading to lodging of FIR, during any election for Lok Sabha or State Legislative Assembly in last five years.
- (vi) PSs with higher than constituency average % of Absentee, Shifted and Dead (ASD) voters (*Ref: Constituency Average % of ASD Voters=Total number of ASD Voters in the constituency/ Total number of polling station*)
- (vii) Information regarding abnormal law and order situation in any particular area.